दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काज़ी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२०० वा | शुक्रवार २१ फ़रवरी २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रुपये | पन्ने - ४

कृषि मंत्री रहते धनंजय मुंडे ने की करोड़ों की हेराफेरी-विधायक सुरेश धस का बड़ा आरोप

एसआईटी जांच की मांग, सीबीआई और ईडी से शिकायत करेंगे

आष्टी, २० फरवरी (प्रतिनिधि):

पूर्व कृषि मंत्री धनंजय मुंडे पर विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा विधायक सुरेश धस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि मुंडे और उनकी टीम ने ३०० करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने सरकार से एसआईटी (विशेष जांच दल) बनाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।

विधायक सुरेश धस ने लगाए ये बड़े आरोप

विधायक सुरेश धस ने धनंजय मुंडे पर कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि - नैनो यूरिया में २१.२६ करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। डीएपी खाद में ५६.७६ करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। बैटरियों की खरीद में ४५.५३ करोड़ रुपये की अनियमितता की गई। कपास भंडारण बैग की कीमत ५७७ रुपये थी, लेकिन उसे १२५० रुपये में खरीदा गया। मुंडे और उनकी टीम ने कुल १८०.८३ करोड़ रुपये की हेराफेरी की। आज आवेदन, कल कर्ज - टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर का आरोप धस ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे ने बेहद चालाकी से टेंडर निकाले, ताकि किसी को कुछ समझ न आए। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का दिमाग चकरा जाएगा कि किस तरह से टेंडर जारी किए गए। धस ने दावा किया कि - बिना किसी मांग के कृषि विभाग ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की। एक ही दिन में प्रस्ताव भेजा गया और उसी दिन सरकारी निर्णय (जीआर) जारी कर दिया गया। तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गेडाम ने इस प्रक्रिया को डिजिटल ट्रांसफर (डीबीटी) से करने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। विधायक धस ने नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग की धस ने आरोप लगाया कि भारतीय किसान संघ ने इस घोटाले की शिकायत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की थी, लेकिन वाल्मिक कराड ने वह पत्र फाड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास यह पत्र नहीं है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुद इस पर जवाब देना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, वाल्मिक कराड का नार्को टेस्ट किया जाए और सीबीआई, ईडी और एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) से पूरे मामले की जांच कराई जाए। ट्रांसफर में भी हुआ १०० करोड़ का घोटाला विधायक धस ने यह भी दावा किया कि धनंजय मुंडे के कार्यकाल में तबादलों में भी १०० करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा, तबादलों के लिए 'रेट कार्ड' उनके अधीनस्थ अधिकारियों के पास था और यह पूरा पैसा धनंजय मुंडे तक पहुंचाया जा रहा था। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग धस ने कहा कि वे सीबीआई, ईडी और एसीबी को इस मामले में विस्तृत शिकायत देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि धनंजय मुंडे के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की पूरी जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या धनंजय मुंडे के खिलाफ जांच शुरू की जाती है।

मंत्री धनंजय मुंडे को हुआ फेशियल पैरालिसिस

खुद सोशल मीडिया 'एक्स' पर दी जानकारी

मुंबई, २० फरवरी (जमीर काजी):

एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेता और कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में हैं। आज शाम उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द पर बताया कि वे बेल्स फाल्सी (फेशियल पैरालिसिस) नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे लगातार दो मिनट तक बात नहीं कर पा रहे हैं।

धनंजय मुंडे ने द पर अपने पोस्ट में लिखा, १५ दिन पहले डॉक्टर टी.पी. लहाने की निगरानी में मेरी दोनों आंखों की सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने १० दिन तक आंखों का खास ध्यान रखने की सलाह दी थी, जिसमें तेज रोशनी, धूल और सूरज की रोशनी से बचने की हिदायत दी गई थी। इस दौरान मुझे पता चला कि मैं 'बेल्स फाल्सी' नामक बीमारी से ग्रसित हूं। फिलहाल, मेरा इलाज रिलायंस अस्पताल के डॉक्टर अरुण शाह की देखरेख में चल रहा है।

उन्होंने आगे लिखा, इस बीमारी के कारण मैं लगातार दो मिनट तक बोल नहीं सकता। इसी वजह से मैं हाल ही में हुई एक-दो कैबिनेट बैठकों और पार्टी के जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारी पार्टी के नेता एवं उपमुख्यमंत्री अजित पवार को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। मैं जल्द ही इस बीमारी को हराकर जनता की सेवा में लौटूंगा।

क्या है बेल्स फाल्सी?

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, बेल्स फाल्सी एक प्रकार की नसों से जुड़ी समस्या (न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर) है, जो चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों को प्रभावित करती है। इसे फेशियल नर्व या सातवीं क्रेनियल नर्व कहा जाता है। जब इस नर्व को क्षति पहुंचती है, तो चेहर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या पूरी तरह काम करना बंद कर देती हैं, जिससे चेहरा असमान रूप से झुक सकता है या व्यक्ति बोलने में कठिनाई महसूस कर सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह समस्या आमतौर पर अस्थायी होती है और उचित इलाज से व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।वशेष जलपान के साथ हुआ। इस आयोजन को सफल बनाने में स्कूल के शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एकनाथ शिंदे को कार में बम से उड़ाने की धमकी

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। शिवसेना में पहले ही विधायकों और नेताओं की सुरक्षा में कटौती को लेकर नाराजगी थी, और अब यह धमकी सामने आने से माहौल और गर्म हो गया है।

अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोरेगांव और जेजे मार्ग पुलिस को ईमेल भेजकर धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ा दिया जाएगा। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में यह खोडसालपणा (शरारती हरकत) भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। ईमेल में क्या लिखा था?

हिंदी में आए इस धमकी भरे ईमेल में लिखा गया है: एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ा दिया जाएगा। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है।

जांच एजेंसियां सतर्क पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और ईमेल भेजने वाले का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक नेताओं को धमकी भरे फोन कॉल और ईमेल मिलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस बार खुद एकनाथ शिंदे का नाम आने के कारण पुलिस ने त्वरित जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा कटौती के बाद बढ़ी चिंता हाल ही में राज्य सरकार ने विधायकों और नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में काफी कटौती की गई। शिवसेना के कई विधायक इस फैसले से नाराज थे। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं धमकी का कारण सुरक्षा में की गई कटौती तो नहीं है? फिलहाल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

९०० ओबीसी पीएचडी छात्रों की फेलोशिप रद्द, अब जॉइनिंग डेट से मिलेगी राशि

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ९०० ओबीसी पीएचडी छात्रों की फेलोशिप रद्द करने का फैसला किया है। इस नए नियम के तहत अब फेलोशिप की राशि पीएचडी की रजिस्ट्रेशन डेट से नहीं, बल्कि जॉइनिंग डेट से मिलेगी। इस फैसले से वे छात्र प्रभावित होंगे, जो अपनी रजिस्ट्रेशन के समय से वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहे थे।

छात्रों के लिए नई चुनौती

ओबीसी वर्ग के शोधार्थियों को पहले ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जून २०२४ में, पुणे से मुंबई तक एक सप्ताह लंबा मार्च निकाला गया था, जिसमें पीएचडी छात्रों ने फेलोशिप की राशि में देरी का विरोध किया था। यह आंदोलन बार्टी, सारथी और महाज्योति क्रुति समिति जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित किया गया था, जो पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

छात्रों ने सरकार से बकाया फेलोशिप जारी करने और ३० अक्टूबर २०२३ को लागू किए गए सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग की थी। छात्रों का कहना था कि यह आदेश फेलोशिप की संख्या पर अनावश्यक सीमा लगाता है और इन शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को कमजोर करता है।

इस विरोध के बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। सरकार ने लंबित फेलोशिप जारी करने का आश्वासन दिया, लेकिन विवादास्पद आदेश को वापस नहीं लिया। इसके बाद, करीब ३,००० पीएचडी छात्रों को बकाया फेलोशिप मिलने का रास्ता साफ हुआ, और प्रदर्शन को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया।

फेलोशिप में देरी से आर्थिक संकट

इन फैसलों के बावजूद, ओबीसी शोधार्थी फेलोशिप मिलने में देरी के कारण आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। दिसंबर २०२४ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय ओबीसी फेलोशिप योजना (छत्र्ऱ्‌इउ) के तहत आने वाले कई छात्रों को जून २०२४ से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली थी। कुछ छात्र जनवरी २०२४ से ही भुगतान के इंतजार में थे। ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन (-खठड-) ने कहा कि इस देरी का छात्रों की आर्थिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और शोध कार्य पर गंभीर असर पड़ा है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जहां डउ और डढ छात्रों को नियमित रूप से फेलोशिप मिल रही थी, वहीं ओबीसी छात्रों को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी।

१००% फेलोशिप का ऐलान और नई चिंता लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर २०२४ में ओबीसी, एनटी, वीजे और एसबीसी वर्ग के पीएचडी छात्रों के लिए १००% फेलोशिप देने की घोषणा की थी। यह फैसला छात्रों के लिए बड़ी जीत माना गया, क्योंकि इससे उन्हें बिना किसी बाधा के शोध जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मिलनी थी।

हालांकि, अब ९०० ओबीसी छात्रों की फेलोशिप रद्द करने और भुगतान की नई शर्तें लागू करने के सरकार के हालिया फैसले ने एक बार फिर पिछड़े वर्ग के शोधार्थियों के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

आंध्र और तेलंगाना की तर्ज पर रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत देने की मांग–अबू आसिम आज़मी

विधानसभा सत्र की कार्यवाही भी जल्द समाप्त करने की अपील

मुंबई, २० फरवरी (यूएनआई):

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत देने की मांग समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आज़मी ने राज्य सरकार से की है।

गौरतलब है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष रियायत देने का ऐलान किया है, जिसके तहत वे शाम ४ बजे कार्यालय से छुट्टी ले सकेंगे। अबू आसिम आज़मी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी और गैर-सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को भी इफ्तार से पहले जल्द छुट्टी दी जाए।

रमजान के दौरान सफाई और पानी आपूर्ति का विशेष प्रबंध करने की मांग

अबू आसिम आज़मी ने अपने पत्र में यह भी आग्रह किया है कि रमजान के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और दिन में दो बार सफाई कराई जाए। इसके अलावा, उन्होंने इफ्तारी के लिए जरूरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी अपील की है ताकि किसी भी इलाके में जल संकट न हो।

फेरीवालों और फल विक्रेताओं के लिए राहत की मांग

समाजवादी पार्टी के नेता ने यह भी कहा कि रमजान के दौरान फल विक्रेताओं और इफ्तारी का सामान बेचने वाले फेरीवालों के प्रति प्रशासन को नरम रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार मुस्लिम बहुल इलाकों में रेहड़ी-पटरी वालों को परेशान न करे और उन्हें विशेष रियायत दी जाए।

विधानसभा की कार्यवाही भी जल्द समाप्त करने की अपील

अबू आसिम आज़मी ने यह भी मांग की है कि चूंकि अगले महीने महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए रमजान के मद्देनजर सदन की कार्यवाही को शाम में जल्द समाप्त किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी और मुस्लिम कर्मचारियों व व्यापारियों को रमजान के दौरान जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगी।

उस समय वे फिर दिखाई नहीं देंगे–उद्धव ठाकरे

विशेष प्रतिनिधि, मुंबई:

मुझे बार-बार झटके दिए जा रहे हैं। जिन्हें जितने झटके देने हैं, दे लें, लेकिन हम उचित समय पर ऐसा झटका देंगे कि वे फिर कभी दिखाई नहीं देंगे, ऐसा तीखा प्रहार पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को किया।

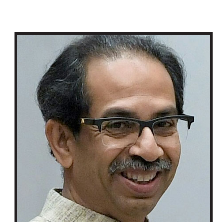

वे कलिना विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और शिवसैनिकों की मातोश्री में आयोजित बैठक में मार्गदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा राजनीतिक हालात का संदर्भ देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कड़ा हमला बोला।

उन्होंने कहा, हर दिन कोई न कोई झटका दे रहा है, इसलिए अब मैं 'धक्का पुरुष' बन गया हूं। देखते हैं, कौन कितने झटके देता है। लेकिन हम एक ही झटका देंगे कि वे फिर कभी नजर नहीं आएंगे।

ठाकरे ने कहा, कोई भी निर्णय लेने पर असहमति होती ही है, लेकिन जब कोई सैनिक होता है, तो उसमें अनुशासन होना जरूरी है। यह लड़ाई किसी अकेले की नहीं है, यह हमारी लड़ाई है। जो लोग हमारी जड़ों पर हमला कर रहे हैं, वे हमारी ही लकड़ी से कुल्हाड़ी बनाकर हमें काटने का काम कर रहे हैं। शिवसेना और मराठी लोगों की जड़ों पर वार किया जा रहा है, इसलिए हमें एकजुट रहना होगा।

उन्होंने आगे कहा, यह समय संगठनात्मक मजबूती का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उम्मीद है, जो २२७ या २३६ धाराओं के अंतर्गत आ सकता है। मुंबई महानगरपालिका चुनाव अप्रैल या मई में होने की संभावना है। सभी कार्यकर्ताओं को शाखा स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। विधानसभा चुनावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए पिछली गलतियों को दोहराने से बचना जरूरी है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

अंजली दमानिया के खिलाफ आपराधिक याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू-धनंजय मुंडे

कैबिनेट बैठक के दस्तावेज़ और मंत्रिमंडल सचिव की मंजूरी के प्रमाण सामने आए

मुंबई, २० फरवरी (प्रतिनिधि):

कृषि विभाग में स्प्रे पंप, सोलर लाइट ट्रैप और अन्य वस्तुओं की खरीद को लेकर धनंजय मुंडे पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। मुंडे ने साफ कहा है कि इस मामले में अंजली दमानिया द्वारा किए गए दावे पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि अंजली दमानिया अधूरी जानकारी के आधार पर झूठे आरोप लगा रही हैं और मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। इसी के तहत उनके खिलाफ आपराधिक याचिका दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कैबिनेट बैठक के दस्तावेजों से आरोप गलत साबित

धनंजय मुंडे ने कहा कि - मुख्य सचिव एवं कैबिनेट सचिव सुजाता सैनिक द्वारा ३० सितंबर को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद २३ सितंबर २०२४ को हुई मंत्रिमंडल बैठक का निर्णय जारी किया गया था।

इस बैठक में कृषि विभाग की खरीद और सीधे आपूर्ति को मंजूरी दी गई थी। अब इस संबंध में वास्तविक दस्तावेज सामने आ गए हैं, जो अंजली दमानिया के दावों को झूठा साबित करते हैं।

मुंडे ने कहा कि जिस पत्र को अंजली दमानिया बिना तारीख का बताया था, वह वास्तव में कृषि मंत्री द्वारा अपने विभाग के सचिव को जारी किया गया एक आधिकारिक नोट था। खरीद प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि - मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस खरीद को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और इसे सरकार के नियमों के तहत ही आगे बढ़ाया जा रहा है।

संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिया गया निर्णय

मुंडे ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६६ के तहत मंत्रियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विभागों को निर्देश दें। इसी के तहत कृषि विभाग को भी निर्देश दिए गए थे।

अंजली दमानिया के आरोप पूरी तरह झूठे - धनंजय मुंडे

उन्होंने कहा, दमानिया ताई ने अधूरी जानकारी के आधार पर जो आरोप लगाए हैं, वे पूरी तरह झूठे हैं और सिर्फ मेरी बदनामी के लिए मीडिया ट्रायल का हिस्सा हैं। मुंडे ने यह भी कहा कि जल्द ही इस मामले में कानूनी कार्रवाई होगी और दमानिया के झूठे आरोपों का पर्दाफाश किया जाएगा।

शिवराय ने अठरापगड़ी जातियों को एकजुट कर स्वराज्य की स्थापना की-सलीम जहांगीर

पेठ बीड़ क्षेत्र में शिवजयंती उत्साह के साथ मनाई गई

बीड़ (प्रतिनिधि) :- देश में सभी जाति-धर्म के लोग आपसी सौहार्द्र के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए जातिगत भेदभाव और विवाद पैदा करने का प्रयास किया है। जाति और उपजाति का कोई भी भेदभाव मानवता को स्वीकार नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अठरापगड़ी जातियों को एकजुट कर स्वराज्य की स्थापना की थी, इसलिए आज उनके विचारों को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आत्मसात करना आवश्यक है। यह मत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सलीम जहांगीर ने व्यक्त किया।

पेठ बीड़ क्षेत्र के गजानन नगर में द्रोणागिरी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव कार्यक्रम में वे बोल रहे थे। इस दौरान शिवजयंती का उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

अपने संबोधन में सलीम जहांगीर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए जातिगत विवाद खड़ा करने का प्रयास किया है, जिससे सामाजिक माहौल खराब होता है। इसलिए सच्चे अर्थों में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आत्मसात करना और सभी जाति-धर्म के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करना आवश्यक है।

उन्होंने यह भी कहा कि गजानन नगर क्षेत्र में सभी जाति-धर्म के लोग सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में रहते हैं और एक-दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे नगरसेवक बनाने के लिए सभी जाति-धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिसके कारण मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत संभव हो सकी।

इस अवसर पर सुदाम शिंदे, साळुंके, गरुड बाप्पू, जयदत्त ठोटे, सुनील काटे, राहुल नागटिळक, एड. सुनील काटे, सुदामराव शिंदे सर, पवार मामा, एड. नितिन शिंदे, नितिन काळे, दळवी सर, दत्ता काटे, गरुड काका, जयदत्त ठोटे, राहुल यादव, अजिंक्य देवडकर, सोमेश्वर मैंदड, सुशांत उपरे, राहुल नागटिळक, मंगेश कदम, प्रसाद पंडित, उमेश कदम, सूरज किंनकर, अमोल कदम, पवन पंडित, गणेश बोचरे सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सिपेट के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश आवेदन प्रक्रिया शुरू

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), २० फरवरी (विकामा) :- केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्था है। महाराष्ट्र में प्लास्टिक उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, इन उद्योगों के लिए आवश्यक कुशल मानव संसाधन विकसित करना और अनुसंधान एवं विकास कार्यों में सहायता करना, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छत्रपति संभाजीनगर में वर्ष २००६ में सिपेट केंद्र की स्थापना की गई थी। सिपेट संस्थान को आईएसओ ९००१:२०१५ प्रमाणन प्राप्त है और यहां एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं एमएसबीटीई के समकक्ष प्लास्टिक इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

सिपेट, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)में कक्षा १०वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी (ऊझढ) और डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी (ऊझचढ) जैसे तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। बीएससी उत्तीर्ण छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेस्टिंग (झत्रऊ-झझढ) नामक दो वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जबकि इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों के लिए पोस्ट डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन (झऊ-झचऊ) नामक १८ महीने का कोर्स किया जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद छात्र प्लास्टिक इंजीनियरिंग में अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं और उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार ९३७३६८७९१५, ९३२५६८७९०२, ०२४०-२४७८३२२ इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

क्राइम ब्रांच की ऐतिहासिक इमारत की जगह बनेगा आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर!

विशेष रिपोर्ट

जमीर काज़ी, मुंबई:

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की ११९ साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत, जो २६/११ के आतंकी हमले के दौरान अजमल कसाब और कई कुख्यात गैंगस्टरों की गिरफ्तारी का गवाह बनी थी, अब इतिहास बन जाएगी। इस पुरानी इमारत का पुनर्विकास कर उसकी जगह मुंबई महानगर पर नज़र रखने वाला एक अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा।

पुनर्विकास के लिए ६० करोड़ का बजट प्रस्तावित

इस पांच मंजिला नई इमारत के निर्माण के लिए ६० करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है, जिसकी व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में की जाएगी। गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

११९ साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत का होगा पुनर्विकास

मुंबई पुलिस आयुक्तालय के परिसर में स्थित क्राइम ब्रांच की मौजूदा इमारत १९०६ से कार्यरत है। इस इमारत में हाजी मस्तान, याकूब लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली जैसे कुख्यात गैंगस्टरों को कभी हिरासत में रखा गया था। १९९३ के बम धमाकों के आरोपी और २६/११ के आतंकी अजमल कसाब को भी पूछताछ के लिए यहीं रखा गया था।

नई इमारत की संभावित विशेषताएं

भूतल: पार्किंग की सुविधा पहली और दूसरी मंजिल: आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तीसरी, चौथी और पांचवीं मंजिल: क्राइम ब्रांच के प्रशासनिक कार्यालय और वरिष्ठ अधिकारियों के कक्ष कैसा होगा नया हाई-टेक कमांड कंट्रोल सेंटर? मुंबई की सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति के लिए एक समर्पित वॉर रूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की दो अत्याधुनिक सुविधाएं सरकारी अधिकारियों के साथ सुरक्षित संचार प्रणाली डेटा सेंटर और हाईब्रिड स्टोरेज सुविधा पावर बैकअप के लिए जनरेटर और यूपीएस सिस्टम एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित निगरानी प्रणाली मुंबई में २४७ अपराध नियंत्रण और निगरानी के लिए ११,००० से अधिक कैमरों का लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम ६० करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित मुंबई पुलिस आयुक्त ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। १० मार्च को पेश होने वाले नए बजट में इस परियोजना के लिए ६० करोड़ रुपये की राशि मंजूर किए जाने की संभावना है।

इस्राइल में भारतीय कामगारों के साथ धोखा, मजदूरों जैसी स्थिति में पहुंचे कुशल श्रमिक

नई दिल्ली: ७ अक्टूबर २०२३ को हमास के हमले के बाद इस्राइल ने हजारों फिलिस्तीनी मजदूरों के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी। इससे निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारी श्रमिक संकट पैदा हो गया। इस कमी को पूरा करने के लिए इस्राइल ने भारत सहित अन्य देशों से कुशल श्रमिकों की भर्ती शुरू की।

भारत से बड़ी संख्या में भर्ती

दिसंबर २०२३ में उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों ने इस्राइल में निर्माण कार्यों के लिए श्रमिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इस योजना के तहत कम से कम १०,००० भारतीय श्रमिकों को इस्राइल भेजने का लक्ष्य रखा गया। इन नौकरियों के लिए १,३७,००० मासिक वेतन का वादा किया गया था, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक आकर्षित हुए।

अनुबंध की सुरक्षा नहीं, श्रमिकों पर पड़ा बोझ

हालांकि, इस योजना में कई खामियां सामने आईं। श्रमिकों के लिए आवास, भोजन और चिकित्सा बीमा जैसी बुनियादी सुविधाओं की लागत उनके वेतन से काटी गई, और यात्रा खर्च भी खुद ही उठाने को कहा गया। सबसे बड़ी चिंता यह रही कि भर्ती प्रक्रिया भारत के 'ई-माइग्रेट' पोर्टल के जरिए नहीं की गई, जो आमतौर पर विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मजदूर संघों ने उठाए सवाल

इस भर्ती प्रक्रिया पर श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने नाराजगी जताई। उन्होंने इसे अमानवीय करार दिया और श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

इस्राइल पहुंचने के बाद बदले हालात

२०२४ की शुरुआत में खबरें आईं कि इस्राइल पहुंचने के बाद भारतीय कामगारों को बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। उनसे लंबे घंटे काम कराया गया, लेकिन वेतन वादे के मुताबिक नहीं दिया गया। कई श्रमिकों ने अपनी पूरी सैलरी तक न मिलने की शिकायत की, क्योंकि कंपनियों ने विभिन्न मदों में कटौतियां कर दीं।

विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा पर सवाल

यह मामला प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में श्रमिकों को भेजने से पहले सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने चाहिए, ताकि वे किसी भी तरह के शोषण का शिकार न हों।

नेशनल उर्दू हाई स्कूल इस्लामपुरा में दसवीं के छात्रों के लिए विदाई समारोह आयोजित

बीड (संवाददाता):

प्रियदर्शिनी एजुकेशन ट्रस्ट के तहत संचालित नेशनल उर्दू हाई स्कूल इस्लामपुरा, बीड में दसवीं कक्षा के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इनामदार रज़ीउद्दीन सर (प्रधानाध्यापक, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल) ने की।

इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फाजिल देशमुख और सहायक शिक्षक क़ाज़ी मुजीबुर्रहमान उपस्थित रहे।

छात्रों ने शिक्षकों के प्रति जताया सम्मान कार्यक्रम में छात्रों और छात्राओं ने अपने अनोखे अंदाज में भाषण प्रस्तुत कर स्कूल और शिक्षकों के प्रति अपनी गहरी भावनाओं का इज़हार किया। इस दौरान रज़ीउद्दीन सर और फाजिल देशमुख ने छात्रों को उपयोगी सुझाव दिए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की सफल व्यवस्था यह आयोजन स्कूल प्रभारी नईम देशमुख की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान दसवीं कक्षा के छात्रों ने प्राइमरी और हाई स्कूल के सभी स्टाफ का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन दसवीं की छात्रा बुशरा बेगम ने बेहतरीन तरीके से किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में फौजिया बाजी, शाहिदा बाजी, मोहम्मदी बाजी और बिलाल देशमुख सर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में नईम देशमुख सर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

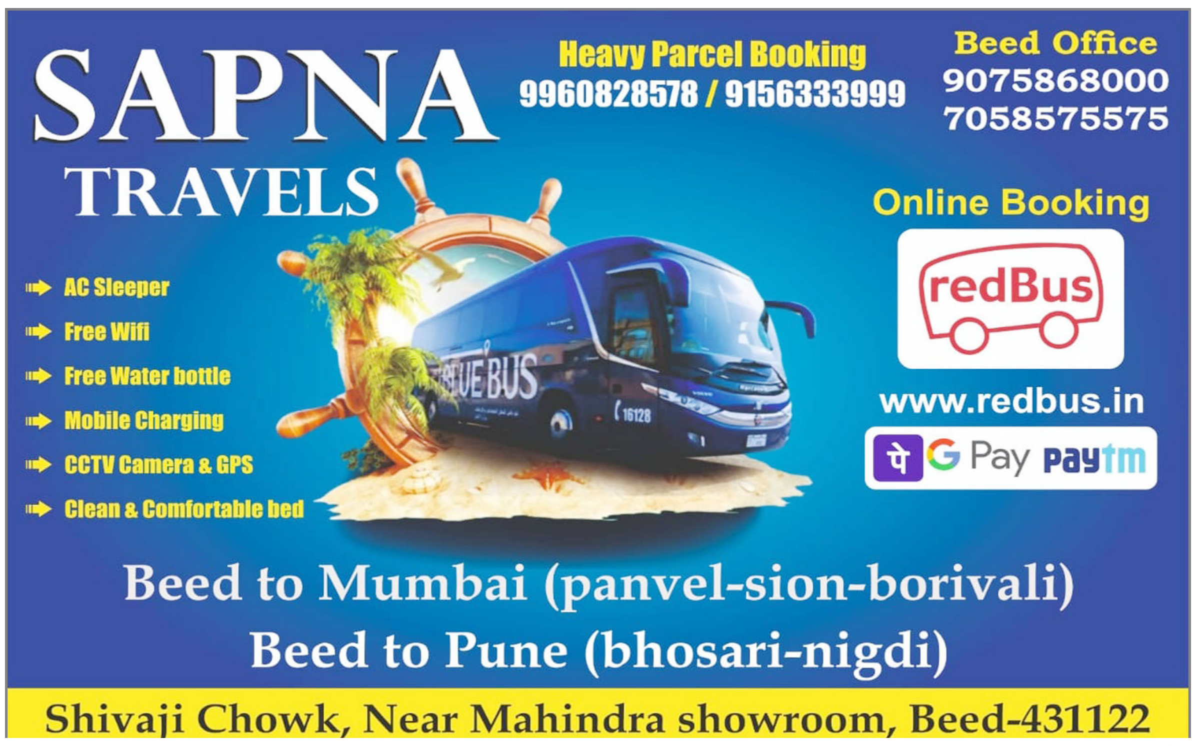

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com